MODEL ANSWER

Q. Discuss the significance of the Minimum Support Price (MSP) system in India. Highlight the advantages and challenges associated with it.

The Minimum Support Price (MSP) is a critical mechanism designed to safeguard farmers against price volatility and market fluctuations. Recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), MSP aims to ensure remunerative prices for farmers while promoting crop diversification and food security.

Significance and advantages of MSP

Economic Stability for Farmers

- MSP provides a safety net against falling market prices, ensuring farmers receive fair compensation for their produce. Further, it plays a crucial role in alleviating rural poverty and reducing farm distress, particularly in drought-prone and disaster-hit areas.

Food Security and Public Distribution

- MSP ensures an adequate supply of food grains for the Public Distribution System (PDS). It stabilizes food prices, benefiting consumers and contributing to national food security objectives.

Encourages Agricultural Investment

- By guaranteeing minimum returns, MSP incentivizes farmers to adopt improved agricultural practices and invest in inputs like seeds, fertilizers, and irrigation. Additionally, a well-implemented MSP mechanism can enhance productivity and sustainability.

Addresses Market Failures

- MSP protects farmers from exploitation by middlemen and ensures their bargaining power in a largely fragmented agricultural market.

Promotes Crop Diversification

- MSP policies for diverse crops aim to encourage farmers to shift from staples like rice and wheat to more sustainable and nutritious crops, such as pulses and oilseeds.

Challenges in the MSP System

Limited Coverage

- While MSP is declared for 23 crops, procurement is heavily skewed towards wheat and rice, leaving farmers of other crops marginalized. For instance, according to the Shanta Kumar Committee report (2015) as of 2021, only 6% of the total number of farmers benefit from MSP.

Environmental Concerns

- Overemphasis on water-intensive crops like rice has led to groundwater depletion and soil degradation in states like Punjab and Haryana.

Burden on Government Finances

- Procuring and maintaining buffer stocks under MSP places a heavy fiscal burden on the government, limiting resources for other developmental activities.

Inefficiencies in Procurement

- Middlemen and inadequate procurement infrastructure hinder farmers from fully realizing MSP benefits. Smaller farmers often remain excluded from the system.

The need of the hour is to enhance the MSP system by setting MSP 50% above the C2 cost, as suggested by the Swaminathan Commission, and implementing the Assured Price to Farmers (APF) system, which combines MSP with profit margins. The Ashok Dalwai Committee stresses the need

Samyak An Institute For Civil Services

for tenancy reforms and market-led agrarian policies. States should amend APMC Acts to support farmer organizations and improve procurement efficiency.

Further, expanding the use of technology, like Karnataka's electronic mandis, can boost market access and price transparency. Additionally, revising MSP to include all production costs, such as family labor and land rent, will ensure fair returns for farmers and promote agricultural sustainability.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्नः भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली के महत्व पर चर्चा करें। इससे जुड़े लाभों और चुनौतियों पर प्रकाश डालें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसे किसानों को मूल्य अस्थिरता और बाजार में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा अनुशंसित और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित, MSP का उद्देश्य फसल विविधीकरण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

MSP का महत्व और लाभ

किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता
- MSP गिरते बाजार मूल्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, MSP यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मुआवजा मिल सके। इसके अलावा, यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करने और विशेष रूप से सूखा-ग्रस्त और आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में कृषि संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण
- MSP सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह खाद्य कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों में योगदान देता है।

कृषि निवेश को प्रोत्साहित करता है
- न्यूनतम रिटर्न की गारंटी देकर, MSP किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने और बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे इनपुट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, एक अच्छी तरह से कार्यान्वित MSP तंत्र उत्पादकता को बढ़ा सकता है।

बाजार की विफलताओं को संबोधित करता है
- MSP किसानों को बिचौलियों द्वारा मनमाने शोषण से बचाता है और कृषि बाजार में उनकी सौदेबाजी की शक्ति को सुनिश्चित करता है।

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है
- विविध फसलों के लिए MSP नीतियों का उद्देश्य किसानों को चावल और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के बजाय दालों और तिलहन जैसी अधिक टिकाऊ और पौष्टिक फसलों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

MSP प्रणाली में चुनौतियाँ

सीमित कवरेज
- जबकि 23 फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है, खरीद में गेहूं और चावल की ओर भारी झुकाव होता है, जिससे अन्य फसलों के किसान हाशिए पर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, शांता कुमार समिति की रिपोर्ट (2015) के अनुसार 2021 तक, कुल किसानों में से केवल 6% ही MSP से लाभान्वित हुए हैं।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ
- चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों पर अत्यधिक ध्यान देने से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल की कमी और मिट्टी का क्षरण हुआ है।

सरकारी वित्त पर बोझ
- MSP के तहत बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, जिससे अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं।

खरीद में अक्षमताएँ
- बिचौलिए और अपर्याप्त खरीद बुनियादी ढाँचा किसानों को MSP लाभों को पूरी तरह से प्राप्त करने से रोकता है। छोटे किसान अक्सर इस प्रणाली से बाहर रह जाते हैं।

समय की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग के सुझाव के अनुसार, C2 लागत से 50% अधिक MSP निर्धारित करके MSP प्रणाली को बढ़ाया जाए और किसानों के लिए सुनिश्चित मूल्य (APF) प्रणाली को लागू किया जाए। अशोक दलवई समिति ने

काश्तकारी सुधारों और बाजार आधारित कृषि नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यों को किसान संगठनों का समर्थन करने और खरीद दक्षता में सुधार करने के लिए APMC अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए।

इसके अलावा, कर्नाटक की इलेक्ट्रॉनिक मंडियों की तरह प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करने से बाजार तक पहुंच और मूल्य पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी उत्पादन लागतों, जैसे कि पारिवारिक श्रम और भूमि किराया को शामिल करने के लिए MSP को संशोधित करने से किसानों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित होगा और कृषि स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

Samyak
An Institute For Civil Services